(2008) 8 **एससीआर** 775

टीडीएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा र प्राइवेटि लटि लमिटेड

बनाम

यूई डेवलपमेंट इंडिया प्राइवेटि लटि लमिटेड

(आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन नं. 2/2008)

मई 14,2008

(एस.बी. सिन्हा, न्यायाधिपति)

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996

सेक्शन 2(1)(एफ)(iii), 11(5),(ए) और 28 - अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता - का अर्थ - मध्यस्थ की नियुक्ति - मध्यस्थता समझौते के दोनों पक्ष भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं – निर्धारित किया : भारत में निगमित एक कंपनी अधिनियम के प्रयोजन के लिए केवल भारतीय राष्ट्रीयता रखती है - एक बार दोनों कंपनियों को भारत में निगमित किया गया है और, इस प्रकार, भारत में अधिवासित है, पार्टियों के बीच और द्वारा किया गया मध्यस्थता समझौता कोई अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता करार नहीं होगा और खण्ड (iii) एस का. 2(1) (एफ) की प्रयोज्यता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा - वर्तमान मामले में, सर्वोच्च अदालत मध्यस्थ नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है - UNCITRAL अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर मॉडल कानून (1985).

विधियों की व्याख्या:

क्षेत्राधिकार का निर्धारण – निर्धारित किया: क्षेत्राधिकार के निर्धारण में एक व्याख्या को निश्चितता सुनिश्चित करनी चाहिए कि विवादित व्यक्ति को 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किस अदालत में जाना चाहिए?- किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के निर्धारण से जुड़े मामले में, निश्चितता बनी रहनी चाहिए जो कि तथ्य के विवादित प्रश्न में प्रवेश करके निर्धारित नहीं किया जा सकता- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 11.

वी वी.आर.एन.एम. सुब्बय्या चेट्टियार बनाम भारत सरकार के आयकर आयुक्त, **मद्रास** 1950 **एससीआर** 961; और मैकलियोड एंड कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (1984) 1 **एससीसी** 434 -**अनुपयुक्त ठहराया गया**.

सुब्बय्या चेट्टियार बनाम आईटी कमिश्नर, **मद्रास एआईआर** 1951 **एससी** 101; और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम राम नारायण, **एआईआर** 1955 **एससी** 36- **संदर्भित।**

डी बीयर्स कंसोलिडेटेड माइन्स लिमिटेड बनाम होवे (करों का सर्वेयर) (1906) **ए सी** 455; यूनिट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम ब्यूलॉक 1960 **ए सी** 351 - **संदर्भित।**

मध्यस्थता पर रसेल, 23 **वां संस्करण**, **पृष्ठ** 357- **संदर्भित।**

मूल सिविल क्षेत्राधिकार: मध्यस्थता याचिका संख्या 2/2008

सुमीत कछवाह, अशोक सागर, धर्मेंद्र, अनुराधा शर्मा एवं मीनाक्षी अरोरा, अपीलकर्ता की ओर से ।

ध्यान चिनप्पा और गौरव अग्रवाल, प्रतिवादी की ओर से ।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया-

1. यहां पार्टियां कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत पंजीकृत और निगमित कंपनियां हैं। हालाँकि, याचिकाकर्ता - कंपनी के निदेशक और शेयरधारक मलेशिया के निवासी बताए जाते हैं। याचिकाकर्ता का निदेशक मंडल भी मलेशिया में बैठता है।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादी को पुनर्वास और उन्नयन के लिए एक अनुबंध दिया गया था। प्रतिवादी ने दिनांक 12.04.2002, 24.05.2002 और 29.08.2002 के तीन प्रदान पत्रों द्वारा याचिकाकर्ता को उसका एक हिस्सा उप-ठेके पर दे दिया।

हालाँकि, वर्तमान याचिका के प्रयोजन के लिए, हम दूसरे और तीसरे प्रदान पत्रों से सम्बद्व हैं। पार्टियों ने उन अनुबंधों में प्रवेश किया जिनमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है, जो निम्नानुसार है:

"यदि पक्ष बातचीत के माध्यम से प्रश्न, विवाद या मतभेद को सुलझाने में विफल रहते हैं, तो इसे भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और उसके तहत नियमों और किसी भी वैधानिक संशोधन या

पुन: अधिनियमन जाे समय-समय पर बनाए गए और भेजने के समय वास्तव में लागू हो, के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा । मध्यस्थता की लागत पार्टियों द्वारा सहमत अनुपात में पार्टियों द्वारा वहन की जाएगी। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा। मध्यस्थता कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा।"

3. पार्टियों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न होने पर, उक्त मध्यस्थता समझौते का सहारा लिया गया, जिसके लिए याचिकाकर्ता द्वारा अपने सॉलिसिटर मैसर्स शुक लिन और बोक के माध्यम से दिनांक 22.03.2007 को एक नोटिस भेजा गया था। एक नामांकित व्यक्ति प्रस्तावित किया गया था। इसके जवाब में, प्रतिवादी ने अपने वकील मैसर्स शर्न डेलामोर एंड कंपनी के माध्यम से भी दिनांक 18.04.2007 को एक पत्र द्वारा अपने नामांकित व्यक्ति का प्रस्ताव रखा। हालांकि, प्रतिवादी ने मध्यस्थता के स्थान को नई दिल्ली के स्थान पर कुआलालंपुर, मलेशिया में बदलने तथा विवादों की मध्यस्थता मलेशियाई कानून और मलेशियाई मध्यस्थता अधिनियम, 2005 के अनुसार किये जाने का सुझाव देकर मूल विवाद समाधान और मध्यस्थता खंड में संशोधन का प्रस्ताव दिया। प्रतिवादी के उक्त प्रस्ताव को याचिकाकर्ता ने खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक नामांकित व्यक्ति का प्रस्ताव रखा जिसे भी प्रतिवादी ने अस्वीकार कर दिया और बदले में अपना स्वयं का नामांकित व्यक्ति सुझाया जो याचिकाकर्ता को स्वीकार्य नहीं था।

4. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में "1996 अधिनियम") की धारा 11 (5) और 11 (6) के तहत इस आवेदन के कारण, प्रदान के उपरोक्त दूसरे और तीसरे पत्रों के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच विवादों और मतभेदों पर न्यायनिर्णयन के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की गई है।

5. प्रतिवादी द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि याचिकाकर्ता - कंपनी भारत में पंजीकृत है, इस न्यायालय के पास मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह आग्रह किया गया था कि कंपनी को कानून में भारत में स्थित माना जाना चाहिए, भले ही निदेशक विदेशी नागरिक हों, क्योंकि सभी इरादे और उद्देश्य के लिए, भारत में निगमित कंपनी को हमेशा भारत में नियंत्रित किया जाएगा।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सुमीत कछवाह ने कहा कि 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के साथ पठित धारा 2 (1) (एफ) में निहित प्रावधानों के मद्देनजर, केवल इस न्यायालय को ही एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार है क्योंकि याचिकाकर्ता कंपनी के केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण मलेशिया में किया जाता है क्योंकि "केंद्रीय प्रबंधन" शब्द का अर्थ यह होगा कि इसका दैनिक प्रबंधन भारत में नहीं होता है।

7. इस तथ्य पर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए यह आग्रह किया गया था कि भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 में एक समान प्रावधान है कि इस प्रकृति के मामले में जो परीक्षण लागू किया जाना चाहिए वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा डी बीयर्स कंसोलिडेटेड माइंस लिमिटेड बनाम होवे (टैक्स सर्वेक्षक) [(1906) एसी 455] में प्रतिपादित वास्तविक व्यावसायिक परीक्षण है, जिसे *वीवीआरएनएम सुब्बैया चेट्टियार बनाम आयकर आयुक्त, मद्रास* [1950 *एससीआर* 961] और*मैकलोड एंड कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य* [(1984) 1 *एससीसी* 434] में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

8. श्री कछवाह का मानना है कि "राष्ट्रीयता", "अधिवास" या "निवासी" शब्दों की व्याख्या उस पाठ और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए जिसमें उनका उपयोग किया गया है। इस संबंध में हमारा ध्यान अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1975 की धारा 1 (4) और अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के भाग II में होने वाली धारा 85 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया गया है, जो हालांकि, लागू नहीं हुआ है।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री ध्यान चिनप्पा का कहना था कि 1996 के अधिनियम और कर क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या के लिए व्याख्यात्मक उपकरण अलग-अलग हैं।

यह आग्रह किया गया कि इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार 1996 अधिनियम की धारा 2 (6), 11 (9) और 28 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया कि अंग्रेजी अदालतें, कर संबंधी क़ानून के संबंध में भी, अपने पहले के रुख से भटक गई हैं, जैसा कि यूनिट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम बुलॉक [1960 ए सी 351] में एक निर्णय से प्रतीत होता है।

10. 1996 का अधिनियम घरेलू मध्यस्थता, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए और साथ ही सुलह से संबंधित कानून को परिभाषित करने और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।

1996 अधिनियम की प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत की संसद का इरादा 1985 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) द्वारा बनाए गए नियमों को प्रभावी बनाने का था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर अनसिट्रल मॉडल कानून के रूप में जाना जाता है।

11. इससे पहले उल्लेखित प्रश्नों पर विचार करने से पहले, हम 1996 अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं। 1996 अधिनियम की

धारा 2 (1) (ए), 2 (1) (बी), 2 (1) (एफ), 2 (6), 2 (7) और 2 (8) इस प्रकार पढ़ें:

"2 (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए) "मध्यस्थता" का अर्थ कोई भी मध्यस्थता है, चाहे वह स्थायी मध्यस्थ संस्था द्वारा प्रशासित हो या नहीं;

(बी) "मध्यस्थता समझौता" का अर्थ धारा 7 में निर्दिष्ट एक समझौता है ;

(एफ) "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" का अर्थ कानूनी संबंधों से उत्पन्न होने वाले विवादों से संबंधित मध्यस्थता है, चाहे वह संविदात्मक हो या नहीं, भारत में लागू कानून के तहत वाणिज्यिक माना जाता है और जहां कम से कम एक पक्ष है-

(i) एक व्यक्ति जो भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक है, या साधारणतया निवासी है; या

(ii) एक निगमित निकाय जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित है; या

(iii) एक कंपनी या एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय जिसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है;या

(iv) किसी विदेशी देश की सरकार;

(6) जहां यह भाग, धारा 28 को छोड़कर, पक्षकारों को एक निश्चित मुद्दे का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है, उस स्वतंत्रता में शामिल होगा उस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए किसी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करने का पार्टियों का अधिकार।

(7) इस भाग के तहत दिए गए एक मध्यस्थ पंचाट को घरेलू पंचाट माना जाएगा।

(8) जहां यह भाग.-

(ए) इस तथ्य को संदर्भित करता है कि पार्टियां सहमत हैं या वे सहमत हो सकते हैं, या

(बी) किसी अन्य तरीके से पार्टियों के समझौते को संदर्भित करता है, उस समझौते में कोई भी मध्यस्थता नियम शामिल होंगे उस समझौते में उल्लेख किया गया है. "

धारा 11 (1), 11 (5) और 11 (9) इस प्रकार हैं:

"11 - मध्यस्थों की नियुक्ति

(1) किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति मध्यस्थ हो सकता है, जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो।

(5) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समझौते में किसी का असफल होना ,एकमात्र मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता में यदि पक्ष एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो नियुक्ति होगी किसी पक्ष के अनुरोध पर, मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है।

(9) किसी अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश या व्यक्ति या संस्था उसके द्वारा नामित पार्टियों की राष्ट्रीयताओं के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीयता के मध्यस्थ को नियुक्त कर सकता है जहां पार्टियां विभिन्न राष्ट्रीयताओं से संबंधित हैं।"

1996 अधिनियम की धारा 28 इस प्रकार है:

"28 - विवाद के सार पर लागू नियम

(1) जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है, -

(ए) एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य मध्यस्थता में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण भारत में उस समय लागू होने वाले मूल कानून के अनुसार मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत विवाद का निर्णय करेगा;

(बी) अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में -

(i) मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवाद का निर्णय विवाद के सार पर लागू होने वाले पक्षकारों द्वारा निर्दिष्ट कानून के नियमों के अनुसार करेगा;

(ii) किसी दिए गए देश के कानून या कानूनी प्रणाली के पक्षों द्वारा किसी भी पदनाम को, जब तक कि अन्यथा व्यक्त न किया गया हो, सीधे तौर पर उस देश के मूल कानून का संदर्भ माना जाएगा, न कि इसके कानूनों के नियम के टकराव में;

(iii) पक्षकारों द्वारा खंड (ए) के तहत कानून के नामित होने में विफल होने पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवाद के आसपास की सभी परिस्थितियों को देखते हुए कानून के उन नियमों को लागू करेगा जिन्हें वह उचित मानता है।

(2) मध्यस्थ न्यायाधिकरण पूर्व असमानता या सौहार्दपूर्ण समग्र के रूप में निर्णय तभी लेगा जब पार्टियों ने स्पष्ट रूप से ऐसा करने के लिए उसे अधिकृत किया हो।

(3) सभी मामलों में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्णय लेगा और लेनदेन पर लागू व्यापार की प्रथाआेंं को ध्यान में रखेगा। "

12. जबकि 1996 अधिनियम का भाग । घरेलू मध्यस्थता से संबंधित है, भाग ।। विदेशी पंचाट से संबंधित है।

"अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" शब्द का एक निश्चित अर्थ है। इसका अन्य बातों के साथ-साथ तात्पर्य एक कॉर्पोरेट निकाय से है जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, यह एक ऐसी कंपनी है जिसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है और इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी भारत में निगमित और पंजीकृत है, इसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण मलेशिया में किया जा रहा है, यह 1996 अधिनियम की धारा 2 (1) (एफ) के खंड (iii) के दायरे में आएगा।

13. जब भी किसी व्याख्या खंड में, "साधन" शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे एक प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया जाना चाहिए।

"अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" और "घरेलू मध्यस्थता" दो अलग-अलग चीजों को दर्शाते हैं। 1996 का अधिनियम घरेलू मध्यस्थता को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के दायरे से बाहर करता है। जो कंपनी भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित हुई है उसे उक्त परिभाषा से बाहर रखा गया है। इसे दोबारा इस आधार पर शामिल नहीं किया जा सकता कि इसका केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण भारत के अलावा किसी अन्य देश में किया जाता है। हालाँकि 1996 अधिनियम की धारा 2 (1) (एफ) का खंड (iii) एक ऐसी कंपनी की बात करता है जिसमें आम तौर पर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत और निगमित कंपनी शामिल होगी, लेकिन इसमें एक एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय भी शामिल हो सकता है जो एक विदेशी कंपनी हो। 1996 अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (6) पार्टियों को कुछ मुद्दों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती है। उस स्वतंत्रता में किसी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति को इसे निर्धारित करने के लिए अधिकृत करने का पार्टियों का अधिकार शामिल होगा। इस प्रकार, इस प्रकृति के मामले में, अदालत शब्दों की ऐसी व्याख्या नहीं करेगी जो पक्षकारों के इरादे के विपरीत हो।

एक क़ानून जो पार्टियों और एक कर क़ानून के बीच मध्यस्थता का प्रावधान करता है, उसकी अलग-अलग व्याख्या की जानी चाहिए। "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" शब्द को UNCITRAL मॉडल कानून में

भी जगह नहीं मिलती है। इसे केवल अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम में जगह मिलती है जिसे भी प्रभावी नहीं बनाया गया है।

14. 1996 अधिनियम का भाग II विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन से संबंधित है। क़ानून की योजना को ध्यान में रखते हुए 1996 के अधिनियम को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। यह विभिन्न स्थितियों पर विचार करता है। मध्यस्थ नियुक्त करने की इस अदालत की शक्ति 1996 अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (12) के मद्देनजर तभी उत्पन्न होगी जब यह माना जाए कि विवाद एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के संबंध में उत्पन्न हुआ है।

इस प्रकार, क्या कोई समझौता 1996 अधिनियम की धारा 2 (1) (एफ) के दायरे में आता है, यह मुख्य प्रश्न है। धारा 2 (1) (एफ) भारत में लागू कानून के तहत कानूनी संबंध की बात करती है, चाहे वह वाणिज्यिक हो या अन्यथा। धारा 2 (1) (एफ) के खंड (i) में निर्दिष्ट अनुसार संबंध ऐसे व्यक्ति के बीच होना चाहिए जो भारत के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक है या साधारणतया निवासी है। मेरे विचार में, भारत के अलावा किसी भी देश में किसी कॉर्पोरेट निकाय के संबंध में 'राष्ट्रीयता' या 'साधारणतया निवासी' होने को एक समान अर्थ प्राप्त होना चाहिए।

15. मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में पार्टियों की राष्ट्रीयता का निर्धारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिनियम के प्रयोजन के लिए

भारत में निगमित कंपनी के पास केवल भारतीय राष्ट्रीयता हो सकती है। यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में निगमित किसी कंपनी के पास भारतीय राष्ट्रीयता नहीं है। इसलिए, जहां दोनों पक्षों के पास भारतीय राष्ट्रीयताएं हैं, तो ऐसे पक्षों के बीच मध्यस्थता को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता नहीं कहा जा सकता है।

16. विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि शब्द "या" विघटनकारी होने के कारण, 1996 अधिनियम की धारा 2 (1) (एफ) का खंड (iii) उस मामले में लागू होगा जहां खंड (ii) लागू नहीं होगा। हम सहमत नहीं हैं। खंड (iii) का सहारा लेने का प्रश्न केवल उस मामले में आएगा जहां खंड (ii) अन्यथा पूरी तरह से लागू नहीं होता है और ना कि जहां बहिष्करण खंड के कारण किसी समझौते को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मानने पर विचार किया जाता है, मध्यस्थता समझौता इसकी परिभाषा के दायरे से बाहर हो जाता है। एक बार जब यह माना जाता है कि दोनों कंपनियां भारत में निगमित हैं, और इस प्रकार, वे भारत में अधिवासित हैं, तो उनके बीच और उनके द्वारा किया गया मध्यस्थता समझौता एक अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता समझौता नहीं होगा और, इस प्रकार, धारा 2 (1) (एफ) का खंड (iii) की प्रयोज्यता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा।

इसके अलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश को, 1996 अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (9) को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ की राष्ट्रीयता को ध्यान में रखना चाहिए। संबंधित

पक्षों की राष्ट्रीयता को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ की राष्ट्रीयता को ध्यान में रखना पड़ सकता है।

17. केवल ऐसे मामले में, जहां हालांकि एक निकाय कॉर्पोरेट जिसे कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत और निगमित कंपनी होने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण के लिए, एक संघ या व्यक्तियों का निकाय, किसी में केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों को भी ध्यान में लिया जा सकता है।

18. 1996 अधिनियम का अध्याय VI एक मध्यस्थ पंचाट देने और इस संबंध में कार्यवाही को समाप्त करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।'अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता' के संबंध में, 1996 अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) का खंड (बी) लागू होगा, जबकि किसी अन्य विवाद के संबंध में जहां मध्यस्थता का स्थान भारत में स्थित है, उपधारा (1) का खंड (ए) लागू होगा।

19. इस प्रकार, जब दोनों कंपनियों को भारत में शामिल किया जाता है, तो मेरी राय में, धारा 2(1) (एफ) का खंड (ii) लागू होगा, न कि खंड (iii)।

20. 1996 अधिनियम की धारा 28 उसकी धारा 2(6) अनिवार्य है, जो इसे उन प्रावधानों से बाहर करती है जिनका पार्टियां उल्लंघन करती हैं (यदि ऐसा अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है)।विधायिका की मंशा स्पष्ट

प्रतीत होती है कि भारतीय नागरिकों को भारतीय कानून का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह देश की सार्वजनिक नीति का हिस्सा है.

21. रसेल ऑन आर्बिट्रेशन, 23 वां संस्करण, पृष्ठ 357, अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 पर अपनी टिप्पणी में, दर्शाता है कि यद्यपि घरेलू और गैर-घरेलू मध्यस्थता के बीच अंतर किया गया है, लेकिन घरेलू मध्यस्थता से संबंधित प्रावधान प्रभाव में नहीं लाए गए हैं।

22. अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 85 जो घरेलू मध्यस्थता समझौते के संबंध में भाग । में संशोधन का प्रावधान करती है, इस प्रकार है:

> "85.- घरेलू मध्यस्थता समझौते के संबंध में भाग । का संशोधन
>
> (1) घरेलू मध्यस्थता समझौते के मामले में भाग । के प्रावधानों को निम्नलिखित धाराओं के अनुसार संशोधित किया गया है।
>
> (2) इस उद्देश्य के लिए "घरेलू मध्यस्थता" समझौता" का अर्थ एक मध्यस्थता समझौता है जिसमें कोई भी पक्ष शामिल नहीं है -

(ए) एक व्यक्ति जो यूनाइटेड किंगडम के अलावा किसी अन्य राज्य का नागरिक है, या साधारणतया निवासी है, या

(बी) एक निगमित निकाय जो इसमें शामिल है, या जिसका केंद्रीय नियंत्रण और प्रबंधन यूनाइटेड किंगडम के अलावा किसी अन्य राज्य में किया जाता है, और जिसके तहत मध्यस्थता की सीट (यदि सीट निर्दिष्ट या निर्धारित की गई है) यूनाइटेड किंगडम में है।

(3) उपधारा (2) में "मध्यस्थता समझौता" और "मध्यस्थता की सीट" का वही अर्थ है जो भाग । में है (धारा 3, 5 (1) और 6 देखें)।"

अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम, 1975 की धारा 1 की उपधारा (4) भी इसी प्रभाव वाली है।

23. यह ध्यान रखना कुछ महत्वपूर्ण है कि 1996 का अधिनियम एक पक्ष के भारत से बाहर होने पर जोर देता है। घरेलू मध्यस्थता समझौते के प्रयोजन के लिए अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम में एक निगमित निकाय को शामिल नहीं किया गया है और जिसका केंद्रीय नियंत्रण या प्रबंधन यूनाइटेड किंगडम के अलावा किसी अन्य राज्य में किया जाता है।

24. इस प्रकार, अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम के तहत, जिस पर विचार किया जा रहा है वह घरेलू मध्यस्थता समझौता है जहां एक निकाय कॉर्पोरेट को यूनाइटेड किंगडम के अलावा किसी अन्य राज्य में शामिल किया गया है; जबकि 1996 के अधिनियम के तहत केवल एक कॉर्पोरेट निकाय जो केवल भारत के बाहर किसी राज्य में शामिल किया गया है, को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अर्थ में शामिल किया जाएगा।

25. मेरी राय में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का संदर्भ उचित नहीं है। कर क़ानून एक अलग उद्देश्य के लिए अधिनियमित किए जाते हैं। वे अनिवार्य वसूली का प्रावधान करते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 6 स्पष्ट रूप से बताती है कि धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ii) के तहत विचार की गई स्थिति केवल उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए है। यह दो आकस्मिकताओं के बारे में बात करता है, अर्थात्, जहां कंपनी एक भारतीय कंपनी है और जिसके मामलों का नियंत्रण और प्रबंधन पूरी तरह से भारत में स्थित हो सकता है। इसलिए, मेरी राय में, 1996 अधिनियम के प्रावधान भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।

26. ऐसे मामले में भी जहां कर निर्धारण कानून लागू होता है, करदाता की राष्ट्रीयता या अधिवास को ध्यान में रखना पड़ सकता है।

27. इस प्रकार, श्री कछवाह द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।

28. एक व्याख्या को क्षेत्राधिकार के निर्धारण में निश्चितता सुनिश्चित करनी चाहिए कि अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विवादित व्यक्ति को किस अदालत में जाना चाहिए। अन्यथा, यह सवाल हमेशा उठता रहता है कि क्या कोई कंपनी भारत के बाहर नियंत्रित होती है या नहीं और यदि कोई आपत्ति उठाई जाती है तो प्रत्येक मामले में तदनुसार निर्णय लेना होगा। अधिनियम की व्याख्या, जैसा कि यहां पहले सुझाया गया है, निश्चित रूप से उच्च न्यायालय या इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करेगी।

सुब्बय्या चेट्टियार बनाम आईटी कमिश्नर, मद्रास [*ए आइ आर* 1951 *एससी* 101] में, इस न्यायालय ने हिंदू अविभाजित परिवार और परिवार के निवास के मुद्दे से निपटते हुए पतंजलि शास्त्री जे की परिभाषा का समर्थन किया। (मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष इसी मामले में) इस प्रकार है:

> "'नियंत्रण और प्रबंधन', वर्तमान संदर्भ में, नियंत्रण और निर्देश देने वाली शक्ति, 'सिर और मस्तिष्क' को दर्शाता है, जैसा कि इसे कभी-कभी कहा जाता है, और 'स्थित' का तात्पर्य कुछ हद तक स्थायित्व के साथ किसी विशेष स्थान पर ऐसी शक्ति के कामकाज से है, जबकि 'पूरी तरह से' ऐसी

शक्ति की सीट को दो अलग और अलग स्थानों के बीच विभाजित करने की संभावना को मान्यता दी जाएगी।"

उस मामले में, यह न्यायालय, आयकर अधिनियम की धारा 4 में निहित परिभाषा से निपटते समय मुख्य रूप से एक हिंदू अविभाजित परिवार से सम्बद्व था, न कि किसी कंपनी से। इसके अलावा, पतंजलि शास्त्री, जे. के निष्कर्षों में, "कुछ हद तक स्थायित्व" का सीधा संदर्भ है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम राम नारायण [*ए आइ आर* 1955 *एससी* 36] मामले में इस न्यायालय द्वारा (हालांकि एक अलग संदर्भ में) अधिवास की स्पष्ट परिभाषा रखने में एक कठिनाई देखी गई है :

> "निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लेखक इस बात से सहमत हैं "अधिवास" की पूर्ण परिभाषा देना असंभव है। इस अभिव्यक्ति की सबसे सरल परिभाषा चिट्टी,जे. द्वारा *क्रेग्निश बनाम क्रेग्निश* में दी गई है, जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने कहा:
>
> "वह स्थान उचित रूप से किसी व्यक्ति का अधिवास है। जिसे वहां से हटाने के किसी वर्तमान इरादे के बिना उसका निवास स्थान तय किया गया है। "
>
> लेकिन यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है। सच्चाई यह है कि "अधिवास" शब्द का प्रयोग उदाहरणों के लिए किया जाता

है, परिभाषा के लिए नहीं। जैसा भी हो, अधिवास के अस्तित्व के लिए अंग्रेजी कानून द्वारा आवश्यक दो घटक तत्व हैं: (1) एक विशेष प्रकार का निवास, और (2) एक विशेष प्रकार का इरादा। यहां तथ्य अवश्य होना चाहिए और आधिपत्य भी होनी चाहिए। निवास निरंतर नहीं होना चाहिए बल्कि यह अनिश्चित होना चाहिए, न कि पूर्णतः क्षणभंगुर। इरादा उस देश में हमेशा के लिए निवास करने का वर्तमान इरादा होना चाहिए जहां निवास लिया गया है। यह भी एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्थापना है कि किसी व्यक्ति के पास कोई घर नहीं हो सकता है, लेकिन वह अधिवास के बिना नहीं रह सकता है और कानून उसे ऐसे देश में अधिवास मान सकता है जहां वास्तव में उसका निवास नहीं है। एक व्यक्ति तब आवारा हो सकता है जब वह नौका में रहता है या एक यूरोपीय होटल से दूसरे यूरोपीय होटल तक घूमता है, लेकिन फिर भी कानून मनमाने ढंग से उसे एक विशेष क्षेत्र में अधिवास मान लेगा। इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति बिना मूल निवास के नहीं रह सकता, कानून प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म के समय मूल निवास स्थान प्रदान करता है। यह तब तक लागू रहता है जब तक एक नया अधिवास प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, ताकि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल देश को फिर कभी न

लौटने के निस्संदेह इरादे के साथ छोड़ता है, तब भी उसका मूल निवास तब तक उसका बना रहता है जब तक कि वह वास्तव में कुछ में अपेक्षित इरादे के साथ अन्य देश में बस नहीं जाता है।"

यूनिट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (*सुप्रा*) में इस सवाल पर कि क्या दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनियों को इंग्लैंड में अधिवासित माना जाएगा, यह कहा गया था:

"माई लॉर्ड्स, एक सीमित देयता कंपनी के सामान्य संविधान में मैंने संदर्भ नहीं पढ़ा है कि*डी बीयर्स मामले* में लॉर्ड लोरबर्न द्वारा बताए गए परीक्षण में कोई भी अतिरिक्त जोड़ने के इरादे रखती हो। मुझे लगता है कि सर रेमंड एवरशेड यही कह रहे थे कि, लगभग हर मामले में, लिमिटेड कम्पनी के एसोसिएशन के लेख कंपनी का नियंत्रण निदेशक मंडल में निहित करती है और तदनुसार, यदि आपको पता चलता है कि किसी कंपनी का बोर्ड साधारणतया किसी विशेष देश में मिलता है, तो आप इस प्रकार उस कंपनी का निवास तय कर लेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्तमान जैसे किसी मामले को ध्यान में नहीं रखा था, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि लेखों के तहत नियुक्त निदेशक मंडल अब प्रश्न में मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक

अवधि के दौरान बिल्कुल भी नहीं मिले थे, न ही वह इस बारे में कोई राय व्यक्त कर रहे थे कि सही निष्कर्ष क्या होगा, उदाहरण के लिए, नियंत्रण बोर्ड में नहीं बल्कि प्रबंध एजेंटों में निहित था। मुझे ऐसा लगता है कि, मामले में बताई गई परिस्थितियों में, आयुक्त, यदि अपील की अदालत कानून के अनुसार सही थी, लेकिन अपीलकर्ता कंपनी द्वारा की गई स्वीकृति के लिए, यह पता लगाने के लिए मजबूर किया गया है कि अफ्रीकी सहायक कंपनियों का कहीं कोई निवास नहीं था। इसके अलावा, यह पूछा जा सकता है कि यदि प्रत्येक अफ्रीकी कंपनी का व्यवसाय उनके विधिवत नियुक्त बोर्डों द्वारा संचालित होता तो क्या स्थिति होती, लेकिन लेखों की उपेक्षा करते हुए, सभी बोर्ड बैठकें लंदन में आयोजित की गईं और सभी निर्देश लंदन से जारी किये गए। तार्किक रूप से, यदि अपील की अदालत सही थी, तो इन बैठकों की उपेक्षा की जानी चाहिए और अफ्रीकी सहायक कंपनियों को इंग्लैंड में निवासी नहीं माना जा सकता था, लेकिन क्राउन के वकील ने अपने तर्क को इस तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने से इनकार कर दिया। क्राउन के वकील ने सुझाव दिया कि, जब तक लॉर्ड लोरेबर्न के सिद्धांत को वर्तमान मामले में अपील न्यायालय की व्याख्या के अनुसार लागू नहीं किया जाता, परिणाम विनाशकारी होंगे और

कंपनियां नियंत्रण को इधर-उधर ले जाकर अपनी देनदारी को बदल सकती हैं। माई लॉर्ड्स, इसलिए यदि वे प्रासंगिक लेखों में संशोधन करते हैं (सौ प्रतिशत सहायक कंपनी के मामले में बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है), तो वे अपील न्यायालय के दृष्टिकोण पर भी ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अपील न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की व्याख्या को अपनाने से अजीब परिणाम हो सकते हैं जिनका मैंने पहले ही संकेत दिया है।माय लॉर्ड्स, मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड लोरबर्न द्वारा निर्धारित परीक्षण और उसके अनुप्रयोग का पालन, जैसा कि मैं सोचता हूं, अब तक अपनाया गया है, अर्थात् यह प्रश्न कि केंद्रीय नियंत्रण वास्तव में कहां रहता है, यह तथ्य का प्रश्न है आयुक्तों के निर्णय से किसी भी विनाशकारी परिणाम होंगे। आपके आधिपत्य के समक्ष मामले के तथ्य अत्यंत असामान्य हैं। मूल कंपनी के लिए नियंत्रण हथियाना निश्चित रूप से असाधारण है; यह आम तौर पर सहायक कंपनियों के बोर्डों के माध्यम से संचालित होता है, और यदि आयुक्तों ने वर्तमान मामले में पाया होता कि वास्तव में यही हुआ था, तो यह अच्छी तरह से हो सकता है कि आपके आधिपत्य उस निष्कर्ष को परेशान नहीं कर सकते थे।लेकिन उन्होंने इसके विपरीत पाया है, और,

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके निष्कर्ष को सही ठहराने वाले सबूत थे।"

एक कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते किसी कंपनी का अधिवास क़ानून की प्रकृति और उद्देश्य पर निर्भर करेगा।[*मैकलियोड एंड कंपनी लिमिटेड* (*सुप्रा*) *देखें*]।

हालाँकि, उक्त निर्णय में, यह देखा गया है कि किसी कंपनी की राष्ट्रीयता उस देश के कानून द्वारा निर्धारित की जाती है जिसमें इसे शामिल किया गया है और जिससे इसे अपना व्यक्तित्व प्राप्त होता है। हालाँकि, कराधान के उद्देश्य से, निवास का परीक्षण उचित नहीं हो सकता है, बल्कि जहां कंपनी अपना वास्तविक व्यवसाय करती है और जहां केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण मौजूद है। इस प्रकार, कानून में राष्ट्रीयता और निवास के बीच एक अंतर मौजूद है। इसके अलावा, इस बात पर भी विवाद है कि बोर्ड की सभी बैठकें केवल मलेशिया में होती हैं। किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के निर्धारण से जुड़े मामले में, निश्चितता बनी रहनी चाहिए जिसे तथ्य के विवाद प्रश्न में प्रवेश करके निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

29. उपरोक्त कारणों से, मेरी राय है कि इस न्यायालय के पास मध्यस्थ को नामित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। आवेदन लागत सहित खारिज किया जाता है। वकील की फीस 50,000/-रुपये निर्धारित की गई।

आर.पी.

आवेदन खारिज किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से **न्यायिक अधिकारी श्री अमित कुमार (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****